विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। –इटैलियन कहावत

बढ़ते अपराध और बेरोज़गारी

गत कुछ समय से शायद ही कोई दिन ऐसा निकलता होगा, जब समाचार पत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं अन्य शहरों में विभिन्न प्रकार के अपराधों के समाचारों से रंगे नहीं रहते हों। इन अपराधों में हत्या, आत्महत्या, डकैती, धोखाधड़ी, बैंक से धोखा करके पैसा निकालना आदि आदि प्रमुख हैं। ऐसेअनेक प्रकार के अपराध हैं जो शहर में प्रतिदिन हो रहे हैं। पहले तो इस प्रकार के अपराधों से लोग चिंतित होते थे और ऐसी एक भी घटना चर्चा में रहती थी। लेकिन अब तो इसे एक प्रकार से लोगों ने अपनी नियति ही मान लिया है।

मेरे घनिष्ठ मित्र की पत्नी, बापूनगर जैसे पॉश इलाके में शाम के समय घूमने के लिए गई थी। लगभग 6:00 बजे के आसपास दो मोटरसाइकिल सवार तेजी से पीछे से आकर उनके कंधे पर लटका पर्स जोर से खींचकर निकाल कर ले गए और इस छीना-झपटी में वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गई। पर्स में मोबाइल और कुछ पैसे थे। इस घटना के बाद जब प्रत्यक्षदर्शियों में से एक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा उसे यह कह दिया गया कि जिस व्यक्ति के चोट लगी है वह आकर रिपोर्ट दर्ज करे। कितनी विचित्र बात है कि जो महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर गई थी, उससे कहा जा रहा था कि वह थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाए।

जिस तेजी से इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, यह केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अपितु इसके मूल में युवाओं की भयंकर बेरोजगारी, विशेषकर शिक्षित युवाओं की है। हाल में 'कौन बनेगा करोड़पति' में एक प्रतिभागी भीलवाड़ा का था जिसने परिवार की स्थिति खराब होने के बावजूद एम.ए. किया था किंतु बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण मंडी में अनाज की बोरियां ढोने का काम करने के लिए बाध्य था। प्रतिदिन 300 बोरियां उठाकर वह जैसे-तैसे 300 रुपये रोज़ के कमा लेता है। अनेक बार पढ़ने में आता है कि M.A , B Ed करने के बाद युवाओं को 5-6000 रुपये की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। एक चपरासी के पद के लिए हजारों लोग आवेदन करते हैं। राजस्थान में शिक्षक भर्ती तो मज़ाक बन कर रह गई है। सालों के बाद परिक्षा होती भी है, तो पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। जो पढे-लिखे बेरोजगार कर्जा लेकर महीनों तक कोचिंग लेकर तैयारी करने के बाद, बड़ी आशा के साथ परीक्षा देते हैं, परीक्षा रद्द होने पर उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। इनमें से कई मानसिक अवसाद में आत्महत्या कर लेते हैं।

बढ़ते अपराधों की मूल में भी यही बेरोजगारी है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, नौकरी न मिलना या कोई काम-धंधा भी ना होना, युवाओं को एक प्रकार से मजबूर कर रहा है कि वह अपराध की घटना में लिप्त हों। इनमें से कभी कोई पकड़े भी जाएंगे और उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल तब होगा जब देश के युवाओं को गरिमा पूर्ण जीवन जीने लायक आय अर्जन करने का अवसर मिलेगा। सरकार की कई नीतियों के परिणाम स्वरूप, कुछ समय पहले तक छोटे-मोटे काम धंधा करके, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यवसाई अपना घर चला लेते थे। साथ ही कुछ लोगों को काम पर भी रख लेते थे। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल फैलने के बाद इनके लिए स्थिति और विकट हो गई है।

जीएसटी का छोटे दुकानदारों, छोटे काम करने वालों पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। हाल ही, एक 40 वर्षीय युवा व्यवसाई ने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आत्महत्या कर ली, क्योंकि बैंक लगातार कर्जा वसूल करने के लिए दबाव डाल रहे थे जिसके कारण परेशान हो कर उसने स्वयं की जीवन लीला ही समाप्त कर ली।

परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या की घटनाएं भी कई हुई हैं। हाल ही में एक दंपत्ति ने अपनी पुत्रियों के साथ आत्महत्या कर ली। इन सब का एक मात्र कारण यह था कि परिवार का मुखिया इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वह अपने छोटे परिवार का लालन पोषण कर सके।

विडम्बना यह है कि एक ओर जहां आय अत्यंत कम हो गई है, रोजगार के अवसर समाप्त से हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई नित्य प्रति दिन बढ़ रही है। इसके फलस्वरूप आम नागरिक पर दोहरी मार पड़ रही है, विशेषकर उन युवाओं पर जो पढ़-लिख तो गए किंतु नौकरी की तलाश में दिन-रात जूते घिसने के पश्चात भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की तो हालत यह है कि एक-एक पद के लिए हजारों लोग प्रार्थना पत्र देते हैं। कुछ कोचिंग माफिया भी इनसे मोटी रकम वसूल करते हैं। इस सबके बाद भी वर्षों तक कोई भर्ती पूरी नहीं हो पाती या कभी कोई होती भी है, तो न्यायालय में जाकर अटक जाती है। कल्पना कीजिए उस बेरोजगार युवा की जो तीन-चार वर्ष तक किसी सरकारी भर्ती के लिए कोचिंग भी करता है, समय भी लगाता है और उसके बाद भर्ती नहीं हो पाती। वैसे भी कुल मिलाकर 1 प्रतिशत लोग भी इनमे सफल नहीं होते। आज का युवा ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस दिशा में जाए और क्या करे?

समाज के प्रबुद्ध वर्ग को चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के समाज की ओर बढ़ रहे हैं एवं किस प्रकार हम युवाओं की समस्याओं से बेखबर होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में, उन्हें युवाओं के सपनों के साथ एवं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा, अन्यथा इसकी कीमत इतनी अधिक होगी कि उसे चुका पाना संभव नहीं होगा।

युवा भारत का गुणगान प्रधानमंत्री जी प्रत्येक मंच पर बड़े गर्व के साथ करते हैं। उनकी स्थिति पर कभी धरातल पर उतर कर सोचने का प्रयास करें तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। साइबर फ्रॉड के मामले भी इसी का परिणाम है। एक और जहां युवाओं के लिए काम के कोई साधन नहीं है, वहीं दूसरी ओर मोबाइल के माध्यम से वह ऐसे धनाढ्य लोगों की जीवन शैली को भी देखते हैं, जो अकूत संपत्ति के कारण, अपने शौक पूरा करने के लिए पैसा पानी की तरह पैसा बहाते हैं। युवाओं की बेरोजगारी उस समय बड़ा विकराल रूप ले लेती है जब युवा उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी इस लायक नहीं बन पाते कि वह अपना स्वयं का एवं परिवार का गुजारा चला सके। फिर, यदि वह अपराध की राह पर चला जाता है, तो दोष उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि व्यवस्था का एवं सरकार का है, जो उसके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाती है। कहने को प्रधानमंत्री जी एवं अन्य नेतागण यह कहते हैं कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती एवं उन्हें स्वरोजगार करना चाहिए। यह सही है, किन्तु क्या कभी किसी ने इस बात को देखा कि स्वरोजगार से कितनी आमदनी कौन कर सकता है? क्या बैंक से पैसा लेकर व्यवसाय करना आसान है?अच्छा होगा यदि बड़े-बड़े नेता गण या प्रधानमंत्री, धरातल की वास्तविकता से रूबरू हों और देखें कि किसी भी साधारण व्यक्ति को, किसी बैंक से लोन लेने में अथवा किसी प्रकार का काम प्रारंभ करने में कितनी परेशानी होती है?

गत दो-तीन वर्षों में कोविड के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है किन्तु दुर्भाग्यवश सरकार इसे स्वीकारने तक को तैयार नहीं है। सरकार द्वारा 28 माह तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटना ही इस बात का प्रमाण है कि भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या के पास खाना, खाने लायक भी आय नहीं है। धर्म की अफीम देकर हम कितने समय तक युवाओं को भ्रमित कर सकते हैं? ऐसा करके सत्ताधारी दल अपनी सत्ता कुछ समय के लिए अवश्य सुनिश्चित कर लें, किंतु समाज में बढ़ते अपराधों पर लगाम नहीं लगा पाएंगे।

बैंक फ्रॉड की घटनाएं भी बहुत बढ़ी हैं। इनके पीछे भी वही कारण हैं, उपयुक्त रोजगार की अनुपलब्धता, बढ़ती महँगाई और तेजी से अमीर बनने की उत्कंठा। पहले जब डिजिटलीकरण नहीं था, कोई फर्जी दस्तखत करता या अंगूठा लगाता था तो उसकी जांच संभव थी। अब ऑनलाइन और डिजिटाइजेशन के युग में, उसको न हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है ना उसको अंगूठा लगाने की। केवल ओ टी पी (पासवर्ड) से उसके खाते से पैसा एक सेकंड में निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में कई लोग अगर अपनी तकनीक का प्रयोग करके धोखाधड़ी कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार तो अच्छे खासे शिक्षित लोग भी हो रहे हैं, जिनमें कुछ आई ए ए स तक शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारी प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती रहती है।

सरकार ने नई शिक्षा नीति घोषित की और इसे आदर्श नीति के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे समय में जब अधिकांश सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों में आधे से अधिक पद रिक्त हैं, किस प्रकार की शिक्षा और कैसी शिक्षा संभव है? सरकार ने हाल ही में नियमित भर्ती के अभाव में संविदा पर 94000 शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखने का की योजना बनाई थी। भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एन वक़्त पर उसे स्थगित कर दिया गया। इससे कितने बेरोजगार युवाओं के सपने टूट कर चूर-चूर हो गए, इसकी कोई तकलीफ किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं हुई। कभी-कभी लगता है कि शासन में बैठे हुए लोग, युवाओं को केवल सत्ता में आने के लिए हथियार बनाकर, उन्हें मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, अथवा अपने हित के लिए उन्हें अपराध जगत में धकेल रहे हैं। यह स्थिति कभी भी विस्फोटक रूप ले सकती है।

यदि बेरोजगारी की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया एवं युवाओं के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई तो नक्सलवाद और आतंकवाद में भर्ती करना सरल हो जाता है। आतंकवाद और नक्सल वाद की समस्या होती है तो हम सारा दोष पढ़े-लिखे युवाओं पर मढ देते हैं। कभी यह सोचने का प्रयास नहीं करते कि कोई भी व्यक्ति इस ओर आकृष्ट तब होता है जब वह ईमानदारी से अपने जीवन यापन करने में भी समर्थ न हो। जब कोई व्यक्ति सदैव शोषण का ही शिकार होता रहे,चाहे वह आर्थिक, भौतिक या शारीरिक हो, तो फिर उससे अधिक समय तक इसे सहन करने की अपेक्षा करना शायद सही नहीं होगा। किसी भी रूप से आतंकवाद या नक्सलवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता, किंतु शासन, युवाओं की समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे यह समझना होगा कि भारत के युवा की प्रमुख समस्या उनकी बेरोजगारी है। उनकी ऊर्जा को सही रूप से उपयोग में लाना शासन की जिम्मेदारी है। उसे इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी होगी कि वह उसके आधार पर एक गरिमा पूर्ण जीवन यापन करने लायक बन सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर समाज में जिस प्रकार की घटनाएं आज हो रही है वह निरंतर बढ़ती ही रहेंगी और भविष्य में समृद्ध परिवार के लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।

समाज के प्रबुद्ध वर्ग को चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार के समाज की ओर बढ़ रहे हैं एवं किस प्रकार हम युवाओं की समस्याओं से बेखबर होते जा रहे हैं। राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में, उन्हें युवाओं के सपनों के साथ एवं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा, अन्यथा इसकी कीमत इतनी अधिक होगी कि उसे चुका पाना संभव नहीं होगा। जब अराजकता की ओर अगर देश बढ़ेगा तो उसका अंत कहां होगा इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि किसी भी बेरोजगार पढ़े-लिखे युवा को दिशा भ्रमित करना एवं गलत कार्य की ओर प्रेरित करना किसी के लिए बहुत ही सरल कार्य हो सकता है।

आइए हम सब इस पर विचार करें और बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को सबसे पहले स्वीकार करें, तथा इसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके लिए सरकार,समाज, उद्योगपतियों, संस्थाओं एवं सभी को साथ आना होगा। तभी हम समरसता पूर्ण, समतामूलक समाज की स्थापना करने में अपना योगदान दे पाएंगे और देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने में भी सफल हो पाएंगे।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

कृषकों को समता मिलेगी तभी उद्यमी बन सकेंगे!

सुचित्रा आर्य

गांव का मुख्य धंधा खेती है और उसकी आज यह दुर्दशा है कि बड़े मध्यम और छोटे सभी किसान खेती में दिलचस्पी खोते जा रहे हैं सामान्य खेती में कृषि संसाधनों और मजदूरी की दरें बढ़ जाने के कारण मुनाफे की कोई गुंजाइश नहीं रही है। थोड़े बहुत जो अभी अपनी हैसियत बनाए हुए हैं उन्होंने सामान्य खेती छोड़कर फल, साग-सब्जी, दूध इत्यादि के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और जिनके लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी और पूंजी है परंतु ऐसे किसानों की संख्या नगण्य है। अधिकांश किसानों के पास है न तो जानकारी है न ही पूंजी है और न ही पूंजी लगाकर प्रतिफल के लिए लंबे अरसे तक प्रतीक्षा करने की क्षमता है। छोटे किसान कृषि मात्र के भरोसे हैं आजीविका चलाने की आशा छोड़ चुके हैं।

बेरोजगारी का एकमात्र तत्कालिक निदान कृषि का आधुनिकरण है, आधुनिकरण से तात्पर्य बड़े पैमाने की खेती से नहीं है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत यूनियन। यहां आधुनिकरण से तात्पर्य कृषि भूमि से नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लेने से है, खेत का छोटा आकार कृषि के आधुनिकरण में बाधक नहीं है ! जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं बनाई जाती की खेती एक लाभप्रद धंधा बन सके तब तक खेती के उन्नतिशील होने की कल्पना नहीं की जा सकती है।

राहुल गांधी कृषकों को उद्यिमता से जोड़ने खेतों के नजदीक कृषि प्रसंस्करण इकाइयां और फूड पार्क विकसित करके किसानों की अतिरिक्त आमदनी में इजाफा करने की आवश्यक्ता को जरूरी मानकर चल रहें हैं जो खेती किसानी के प्रति उनकी गम्भीरता को दर्शाता है। इसी परिपेक्ष में उन्हीं के निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लाई गई है लेकिन नीति में कुछ बाध्यताएं हैं जो राहुल गांधी की मूल भावना को अवतरित नहीं होने दे रही है। इसी नीति के तहत 21 जनवरी 2021 को राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डवल्पमेंट बोर्ड का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य किसानों की अतिरिक्त आय में इजाफ़ा करने के लिए कृषकों एवं कृषि व्यवसायियों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनकर बेहतर सुझाव संकलित करके सरकार को परामर्श स्वरूप दें ताकि कृषि उद्यिमता को बढावा देकर प्रदेश में कृषि उधोग विकसित किये जा सकें तथा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढावा मिल सके।

राहुल गांधी की सोच को पूर्णरूप से यदि लागु करना है तो इस नीति की बुनियादी सरंचना में संशोधन की आवश्यक्ता अनिवार्य रूप से पड़ेगी, क्योंकि नवीन नीति के तहत पूंजीगत लागत पर किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशी (अधिकतम 1 करोड़) एवं अन्य व्यवसायी/फर्म को 25 प्रतिशत अनुदान राशी सरकार की तरफ से देय है। नीति के तहत बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता रखी गई है, व्यक्ति/किसान जो अपना उद्योग या प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहता उसे पहले अपने प्रोजेक्ट की पूंजीगत लागत को बैंक से ऋण के रूप स्वीकृत करवाना होगा उसके बाद बैंक जो भी ऋण राशि स्वीकृत करेगा उसका 50 प्रतिशत भुगतान प्रदेश सरकार अनुदान राशि के रूप में सीधा किसान के खाते में स्थानांतरण की बजाय सबंधित बैंक को भुगतान करेगी ! सरकार अनुदान दे रही है यहां तक तो ठीक है लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी मूल परेशानी बैंको से ऋण स्वीकृत कराने की है।

ऋण लेने पूर्व जो किसान/व्यक्ति सुरक्षा गारंटी डिपॉजिट करवाने तथा अन्य बैंकिग शर्त पूर्ण करने में सक्षम नहीं है तो बैंक ऋण स्वीकृत नहीं करेगा उस स्थिति में वह स्वत: ही अनुदान के लिए अपात्र माना जाएगा। नीती और नीयती की विडंबना देखिए यदि कोई व्यक्ति/किसान अपनी नकदी लगाकर या अपने स्तर पर प्रोजेक्ट शुरू करता है तथा सरकार से अनुदान की अपेक्षा रखता है तो भी बैंकिंग ऋण की अनिवार्यता के चलते इस नीति से सरकारी अनुदान से वचिंत ही रहेगा। बैंक ऋण की अनिवार्यता लागु करके बड़ी चतुराई से किसानों को अलग कर दिया गया है जबकि व्यवसायियों, कारोबारीयों को बैंक ऋण देने में प्राथमिकता देगा जिसका सीधा लाभ किसानों की बजाय व्यापारिक व्यक्तियों को होगा।

किसानों के प्रति जकड़न की नीति है तथा व्यवसायियों के प्रति उदारता की नीति, यह दौहरे मापदंड एक साथ नहीं चल सकते। कृषक महज स्लोगन या नारों से उद्यमी नहीं बनेगा बल्कि उसे समतायुक्त माहौल देना होगा, 2019 की कृषि नीति में संशोधन करके किसानों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

राजनीतिक शक्ति का स्त्रोत आम आदमी है और जब तक आम आदमी को उदारतावादी नीतियों में अपनी खुशहाली नजर नहीं आएगी तब तक वह उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा। यदि किसान को वास्तविक रूप से लाभान्वित करना है तो बैंकिंग ऋण अनिवार्यता को समाप्त करना होगा अन्यथा किसानों को बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। अब तक तो यह नीति औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े लोगो तक ही सीमित है जिनके फलस्वरूप संपन्न वर्ग ही लाभान्वित हो रहा है साधारण किसानों को किसी भी प्रकार की सरकारी रियायतें नहीं मिल पा रही है।

-सुचित्रा आर्य,
उपाध्यक्ष: राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड, जयपुर।

क्या गैस्ट फैकल्टी अब राज्य के स्कूलों में भी?

प्रो. (डॉ.) वीर बहादुर सिंह

राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा के उपरान्त अब गेस्ट फैकल्टी स्कूलों में भी लगाकर विषय पढ़वाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा की रेड़ मारने के उपरांत सरकार को एक अवसर की तलाश थी और वह मिल गया अर्थात स्कूल जहाँ अध्यापकों के अनेक पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे स्कूलों में भी सरकार जब नियुक्तियाँ करने में विफल हो गई, तो अपना मुहं छिपाने के लिए अथवा अन्य कोई उद्देश्य की पूर्ती हेतु गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से उन विषयों की पढ़ाई कराने का साफूगा छोड़ दिया जिनमे अध्यापक नहीं हैं और सरकार नयी नियुक्तियां करने में बिफल हो चुकी है।

सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि जब पद खाली होते हैं, उनको तत्काल बिना समय गवाए क्यों नहीं भरा जा सकता क्या मजबूरी होती है सरकार की? क्या वर्ष में राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिकांश समय बंद अथवा निष्क्रिय हो जाता है? रिक्त पदों को भरने के लिए क्या किसी पंडित अथवा ज्योतिषी से महूर्त निकलवाना पड़ता है? मेरे विचार से पंडितों और ज्योतिषिओं के लिए यह कार्य कुछ मिनिटों का ही होता है।

हाँ, नियुक्ति से पहले जो गुना भाग करने होते हैं या कुछ वांछित समीकरण बनाने पड़ते हैं, तो बात अलग है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि सब जग जाहिर है।

उस क्रिया के समीकरण बिठाने में समय लगता है। इसलिए वांछित सहायकों को मसला सौंपने में कुछ बिलम्ब हो ही जाता है। परन्तु अमुक शिक्षा मंत्री को ऐसी सभी तैयारियां पूर्व में ही क्यों नहीं करके रखनी चाहिए, ताकि चयन प्रक्रिया में अनावश्यक बिलम्ब न हो? इस सन्दर्भ में मैं इस से अधिक और कुछ लिखने के पक्ष में नहीं हूँ।

मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा विभाग में बैठे कतिपय शिक्षा विशेषज्ञ गेस्ट फैकल्टी का अर्थ तो अवश्य जानते होंगे। मैं स्वयं भी सेवा निवृति के पश्चात् सरकार की ऐसी शतरंजी योजनाओं को जानकर भ्रमित हो जाता हूँ।

अभी तक विश्वविद्यालयों में कोंट्राक्टुअल अथवा ठेके पर पढ़ाई का सुना था, वो तरीका भी वास्तव में ठेका विधि न होकर कालांश आधारित मज़दूरी पैटर्न था। अभी भी वह पैटर्न सुचारु रूप से चल रहा है। अब उसमे भले ही बुराइयां अथवा अच्छाइयां हों, जब तक पढ़ने वाले छात्रों को अनुकूल है और उनके अभिवावकों को भी अन्धकार में रख उनके छात्रों को निर्विघ्न पढ़ा कर, परीक्षा करा कर और अंत में डिग्री दिलवा दी जाती है। तो फिर भले ही उन छात्रों को किसी कमी के कारण कोई नौकरी न दे तो शिक्षण संसथान का उसमे क्या दोष हो सकता है? सबका भाग्य तो विधाता लिखता है।

विदेशों के संस्थानों में एक अन्य विधि और अपनाई जाती है जिसे विजिटिंग फैकल्टी/प्रोफेसर कहते हैं। वहां यहाँ जैसी कालांश प्रथा और परिवर्तित ठेका प्रथा का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है। विजिटिंग फैकल्टी/प्रोफेसर एक निश्चित समयावधि के लिए अन्य संसथान में शिफ्ट कर जाता है जहाँ वह अपनीएक्सपेर्टीस/विशेषग्यता से वहां के टीचर और विद्यार्थिओं को लाभान्वित करता है। भारत में उत्पादित व् विकसित शिक्षा पध्यति एक अनूठी विधि ही सदैव रही है। राजस्थान राज्य की स्कूली शिक्षा की विशालता एवं व्यापकता की तरफ दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा मोटे तौर पर तीन भागों में बांटी जा सकती है (1) बेसिक प्राइमरी, (2) सेकेंडरी और (3) सीनियर सेकेंडरी। कक्षाओं के अनुरूप यह वर्गीकरण 1 से 5 कक्षा तक प्राइमरी, 6 से 10 कक्षा तक सेकेंडरी और 11 से कक्षा 12 तक सीनियर सेकेंडरी। पूर्व में सेकेंडरी में एक वर्ग और होता था कक्षा 6 से 8 तक जिसे मिडिल कहते थे। अभी भी अनेक मिडिल स्कूल संचालित अवस्था में मिल जायेंगे।

एक आंकलन के अनुसार राज्य में वर्तमान में 71309 स्कूल संचालित हैं जिनमे 9337490 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इन स्कूलों में विभिन्न 20 से अधिक विषय पढ़ाने के लिए 427836 कई श्रेणिओं के अध्यापक व् अन्य सहायक कार्यरत हैं अथवा होने चाहिए।

विगत कुछ समय पूर्व लोक सेवा आयोग राजस्थान ने लगभग 6000 नियुक्तिओं के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमे 1668 इंग्लिश, 106 उर्दू, 1565 साइंस और 1640 सोशल साइंस में नियुक्तियाँ करनी थी। यह पता नहीं चल पाया कि आयोग ये नियुक्तिआं कर पाया अथवा नहीं?

एक अपुष्ट आंकलन के अनुसार राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 32000 पद रिक्त हैं। जिनमे लगभग 21 विभिन्न विषयों के पद हैं। यह रिक्तियां एक से अधिक बार जारी की गई लेकिन उन पर सरकार कोई नियुक्ति नहीं करवा सकी। और अब प्राथमिकता सरकार की गेस्ट फैकल्टी से काम चलने की प्रतीत हो रही है। जिसके परिणाम तो एक दो वर्ष पश्चात् ही मिल सकेंगे? तब तक नियुक्ति की आशा संजोने वाले अभ्यर्थी प्रतीक्षा ही करें।

तदुपरांत अखवार के माध्यम से कुछ ख़बरें आईं कि अब रिक्त पद गेस्ट फैकल्टी से भरे जायेगे। माथा चकरा गया गेस्ट फैकल्टी का सुनकर। सरकार में सम्बंधित अफसर संभवत: गेस्ट फैकल्टी का अभिप्राय ही नहीं जानते। अंठोजी का शब्द बोलना ऐसे लोग तथाकतिथ शिक्षा प्रबंधन में अपनी योग्यता को दर्शाते दिखते हैं। अच्छा रहे कि शिक्षा विभाग अपने सम्बंधित अफसर और सहायकों का समुचित ओरिएंटेशन कराएं फिर उनको विभाग में कार्य निष्पादित करने का दायुत्व सौंपे। फिर भी सरकार के लिए गेस्ट फैकल्टी को परिभाषित करना जरूरी है।

गेस्ट फैकल्टी विषयवार लगेगी क्या और उस फैकल्टी को उस विषय के कितने कालांश प्रति सप्ताह पढ़ाने होंगे? अथवा पूरा विषय वर्षभर गेस्ट अध्यापक को पढ़ना होगा? अथवा क्या गेस्ट फैकल्टी अपना विषय दो तीन माह में पढ़ा कर उस विद्यालय से मुक्त हो जावेगी? और क्या गेस्ट फैकल्टी को दिए गए पारिश्रमिक से वह संतोष कर लेगा? अथवा एक गेस्ट अध्यापक से एक से अधिक विषय पढवाये जायेंगे? इस प्रकार के अनेक प्रश्न स्कूली शिक्षा में उपज सकते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण पक्ष तो यह है कि गेस्ट अध्यापक की क्या जवाबदेही होगी? यदि उस विषय का फाइनल परीक्षा परिणाम असंतोषजनक पाया जाये? क्योंकि वह तो पढ़ा कर अपना पारश्रमिक लेकर स्कूल से चला जायेगा। एक और बात जो सोचने की है वह कि क्या सोशल साइंस का व्यक्ति कोई अन्य विषय यथा साइंस, इंग्लिश, गणित आदि पढ़ा सकेगा?

इसी प्रकार साइंस का वयक्ति क्या भूगोल इंग्लिश अथवा हिंदी पढ़ा सकेगा? इसलिए राज्य के शिक्षा विभाग को इन सभी पक्षों पर व्यवस्थित तरीके से विचार कर ही गेस्ट फैकल्टी पद्धति अपनाने का निर्णय करना उचित होगा। स्नातक स्तर की कक्षाओं में गेस्ट फैकल्टी से कोई विशेष विषय ही पढ़वाया जाता है।

ऐसे में एक से अधिक विषय पढ़वाने के लिए क्या वांछित विषयों के गेस्ट टीचर स्कूलों में लगाने होंगे? वक्तव्य देना बहुत सुगम है परन्तु जब उसे यथार्थ में लागू करना पड़े तो पसीने छूट जायेंगे। फिर भी मेरी यह अनुशंसा है कि सरकार स्थाई नियुक्तियां बिना समय गवाए शीघ्रता से कर दे जिससे नियुक्ति के इंतज़ार में बैठे हज़ारों बीएड अभ्यर्थी नियुक्त होकर शिक्षण का कार्य संभाल सकें और उत्तरोत्तर अपनी विधा में एक उत्तम टीचर के सभी गुण विकसित कर सकें।

–प्रो. (डॉ.) वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं डेरी विज्ञ,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान।

असिस्टैंट डायरेक्टर पात्रता जांच के लिए विचारित सूची जारी

- **अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जाएगी**
- **अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा**

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गृह (ग्रुप-1) विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर (डीएनए डिवीजन) पदों के लिए संवीक्षा परीक्षा-2021 के तहत पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की गई है। साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सचिव एचएल अटल ने बताया कि आयोग द्वारा इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए संवीक्षा परीक्षा का आयोजन 10 जून को किया गया था। परीक्षा के फलस्वरूप 12 अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच के लिए विचारित सूची में अस्थाई रूप से शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि जारी की गई विचारित सूची साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करना है।

अभ्यर्थियों की पात्रता जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही साक्षात्कार के लिए परिणाम जारी किया जाएगा। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

सहायक आचार्य-ईएएफएम साक्षात्कार तिथि जारी

- **1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक साक्षात्कार किया जाएगा**
- **अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति साथ लाये**

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को सहायक आचार्य- ईएएफएम (कॉलेज शिक्षा विभाग) 2020 के पदों की साक्षात्कार दिनांक जारी की गई। निर्धारित कार्यक्रमानुसार 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

आयोग सचिव एचएल अटल ने कहा कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। विस्तृत आवेदन-पत्र को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने समस्त मूल-प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति अवश्य साथ लाएं। इनके अभाव में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करनी होगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 22 नवम्बर, 2022

मार्गशीष मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2079, स्वाती नक्षत्र रात्रि 11:12 तक, सौभाग्य योग सांय 6:37 तक, वणिज करण प्रातः 8:50 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-तुला, मंगल-वृष, बुध-वृश्चिक, गुरू-मीन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज भद्रा प्रातः 8:50 से सांय 7:52 तक रहेगी। सायन सूर्य धनु में दिन 1:51 पर प्रवेश करेगा। आज चतुरदशी तिथि का क्षय हुआ है। आज मास शिवरात्रि है, आज से राष्ट्रीय मार्गशीर्ष मास आरम्भ होगा।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:34 से 10:53 तक, लाभ-अमृत 10:53 से 1:32 तक, शुभ 2:51 से 4:11 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:55, सूर्यास्त 5:30

मेष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

कर्क
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
धार्मिक-मांगलिक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

धनु
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे।

कुंभ
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी और व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।